THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) No, Sir. The construction of roads including rural roads is a State subject under Minimum Needs Programme (MNP) and funds for the same are being provided in the State Plan/Budget.

(b) to (d) Does not arise.

डकैती उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन सड़कों का निर्माण

@3290. **श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश के डाकू ग्रस्त जिलों में डकैती उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन प्रथम चरण के अंतर्गत 14 सड़कों के निर्माण और द्वितीय चरण के अंतर्गत 61 सड़कों के निर्माण हेतु क्रमशः वर्ष 1984 तथा 1985 में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त सभी सड़कों के निर्माण के लिये धन को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो सभी सड़कों के निर्माण के लिये कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना रिपोर्ट में विशेष समस्या वाले क्षेत्रों (जिन्हें पहले दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था) में सड़कों के निर्माण की योजना के अंतर्गत पहले चरण में 14 सड़कों और दूसरे चरण में 61 सड़कों के निर्माण हेतु अनुमान शामिल किए गए थे। इसमें से, दूसरे चरण की एक सड़क सहित 14 सड़कों को 1985–86 और 1986–87 में अनुमोदित किया गया है। सभी निर्माण कार्य प्रगति पर है। मध्य प्रदेश सरकार से 10 अन्य सड़कों के निर्माण का भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पहले से स्वीकृत निर्माण-कार्यों की असन्तोषजनक प्रगति और राज्य सरकार से आवश्यक स्पष्टीकरण न मिलने के कारण 10 सड़कों के लिये प्रशासनिक अनुमोदन नहीं दिया जा सका था।

इन सड़कों के लिये प्रशासनिक अनुमोदन स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति, निधियों की उपलब्धता और राज्य सरकार से अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

मध्य प्रदेश के विकास केन्द्रों को पक्की सड़कों द्वारा जोड़े जाने का प्रस्ताव

@@3291. **श्री अजीत जोगी :**
श्री बेकल "उत्साही :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से राज्य की जनजातीय पट्टी में स्थित विकास केन्द्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये तकनीकी तथा वित्तीय मंजूरी देने के लिये वर्ष 1983 में 119 करोड़ रुपये के प्राक्कलन प्राप्त हुए थे;

(ख) क्या सरकार ने इन प्राक्कलनों को मंजूरी दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो वांछित स्वीकृति कब तक दिए जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) सड़कों के निर्माण हेतु 119.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक मास्टर प्लान मध्य प्रदेश सरकार से 1983 में प्राप्त हुई थी। उस समय राज्य सरकार से इस

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2599, 16 दिसम्बर, 1991 से स्थानान्तरित।

@@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2579, 16 दिसम्बर, 1991 से स्थानान्तरित।

सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था । 1983–84 में राज्य सरकार ने निम्नलिखित तीन निर्माण-कार्यों के प्रस्ताव भेजे थे जिन्हें भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया गया था :–

(लाख रुपये में)

निर्माण कार्यों का नाम	स्वीकृत लागत
1. अचंकमार-किओंची सड़क	192.27
2. मदवास-कुशमी मार्ग पर 6 पुल और पहुंच सड़कें	170.04
3. मदवास-कुशमी-रुण्डा-भदुरा सड़क	46.35

आदिवासी गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़े जाने की योजना

@3292. **श्री अजीत जोगी :**
श्री बेकल "उत्साही" :
श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आदिवासी क्षेत्रों के 500 लोगों से ज्यादा आबादी वाले गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो आदिवासी क्षेत्रों के कम आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की केन्द्रीय सरकार की क्या योजना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की केन्द्रीय योजना को 1987–88 से बन्द कर दिया गया था।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2580, 16 दिसम्बर, 1991 से स्थानान्तरित ।

Farmers below poverty-line in Arunachal Pradesh

@@3293. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the present number of small and marginal farmers living below the poverty-line in Arunachal Pradesh;

(b) whether Government propose to launch any schemes to improve their living conditions; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) There are 16,267 small farmers and 12,765 marginal farmers living below poverty line in Arunachal Pradesh.

(b) and (c) The following schemes are already being implemented by Government for development of small and marginal farmers—

(i) Integrated Rural Development Programme (IRDP).

(ii) Assistance to Smalj and Marginal Farmers for increasing agricultural production through construction of shallow tube-wells and dug wells on the holdings of small and marginal farmers in the State selected for Special Foodgrain Production Programme (SFPP).

(iii) Establishment of Farmers' Agro-Service Centre and Introduction nad Adoption of Seeding and Planting machines.

(iv) Lab-to Land Programme.

(v) Special Livestock Breeding Programme.

(vi) Integrated Programme for Rice Development.

@@Previously Unstarred Question 2258 transferred from the 13th Dec. 1991.